

माओवादी उग्रवाद का उन्मूलन

प्रलम्बिस् के लयिः

[केंद्रीय रजिस्व पुलसि बल, कमांडो बटालयिन फॉर रेजोलयूट एक्शन, ऑपरेशन समाधान, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम, नागरकि कार्यवाही कार्यक्रम, वन अधिकार अधिनियम, 2006, वधिविरुद्ध करिया-कलाप \(नविवरण\) अधिनियम, 1967, वन संरक्षण अधिनियम, 1980, पाँचवीं और नौवीं अनुसूची, जनजातीय सलाहकार परषिद ।](#)

मेन्स के लयिः

भारत में वामपंथी उग्रवाद से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ ।

[स्रोतः पी.आई.बी](#)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने छत्तीसगढ़ के जगदलपुर स्थति अमर शहीद स्मारक पर [माओवादी उग्रवाद](#) (नक्सलवाद) से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पति की ।

- उन्होंने यह भी कहा कि त्रि-आयामी रणनीति का उपयोग करके मार्च 2026 तक भारत [माओवादी उग्रवाद](#) (नक्सलवाद) से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा ।
 - त्रि-आयामी लालच-और-दंड रणनीति (Three-Pronged Carrot-And-Stick Strategy) में माओवादी उग्रवाद से निपटने के लयि सुरक्षा उपाय, वकिस और सशक्तकिरण शामिल हैं ।

माओवादी उग्रवाद को खत्म करने की त्रि-आयामी रणनीति क्या है?

- सुरक्षा उपाय (बल):
 - सुरक्षा बलों की तैनाति: वामपंथी उग्रवाद (LWE) प्रभावति क्षेत्रों में केंद्रीय और राज्य पुलसि बलों की उपस्थतिको मज़बूत करना ।
 - संयुक्त अभयान: राज्य पुलसि और केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे [CRPF \(केंद्रीय रजिस्व पुलसि बल\)](#) तथा [COBRA \(कमांडो बटालयिन फॉर रेजोलयूट एक्शन\)](#) के बीच समन्वति कार्यवाही ।
 - क्षमता नरिमाण: सैन्य बलों के लयि हथियारों, संचार प्रणालियों और बुनयिदी ढाँचे को उन्नत करना । उदाहरण के लयि, CAPF बटालयिनों के लयि मनि UAV, सौर लाइट, मोबाइल टावर आदि का उपयोग ।
 - ऑपरेशन समाधान: खुफिया जानकारी जुटाने, परिचालन रणनीति और वकिस पर केंद्रति एक दृष्टिकोण ।
- वकिस पहल:
 - वकिस केंद्रति योजनाएँ: प्रमुख कार्यक्रमों का कारयान्वयन जैसे:
 - [PMGSY \(प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना\)](#): ग्रामीण सडक कनेक्टविटी के लयि ।
 - [आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम](#): सरकार ने नक्सल प्रभावति क्षेत्रों में 15,000 घरों के नरिमाण को मंजूरी दी है ।
 - प्रत्येक गाँव में सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का शत-प्रतशित लाभ पहुँचाने के प्रयास चल रहे हैं ।
 - वामपंथी उग्रवाद प्रभावति 47 ज़िलों में कौशल वकिस योजना: वामपंथी उग्रवाद प्रभावति क्षेत्रों के लयि वशिष रूप से तैयार की गई ।
 - नागरकि कार्यवाही कार्यक्रम (CAP): वामपंथी उग्रवाद प्रभावति क्षेत्रों में वभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को करने के लयि CAPFs को वतितीय अनुदान प्रदान करना
 - वशिष अवसंरचना योजना: सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सडक, पुल और स्कूल जैसी बुनयिदी अवसंरचना का सृजन ।
 - बेहतर शासन: स्थानीय कार्मिकों की भरती के माध्यम से इन क्षेत्रों में प्रशासनकि दक्षता बढ़ाना ।
- सशक्तीकरण (दलि और दमिग जीतने का दृष्टिकोण):
 - सार्वजनकि सहभागति: सरकार और जनजातीय समुदायों के बीच वशिवास और संचार को बढ़ावा देना, अलगाव को कम करना ।
 - पुनर्वास नीतियाँ: माओवादी कार्यकर्त्ताओं के लयि आत्मसमर्पण और पुनर्वास योजनाएँ, जनिमंशकिषा, व्यावसायकि प्रशकिषण तथा

वित्तीय सहायता जैसे प्रोत्साहन दिये जाते हैं।

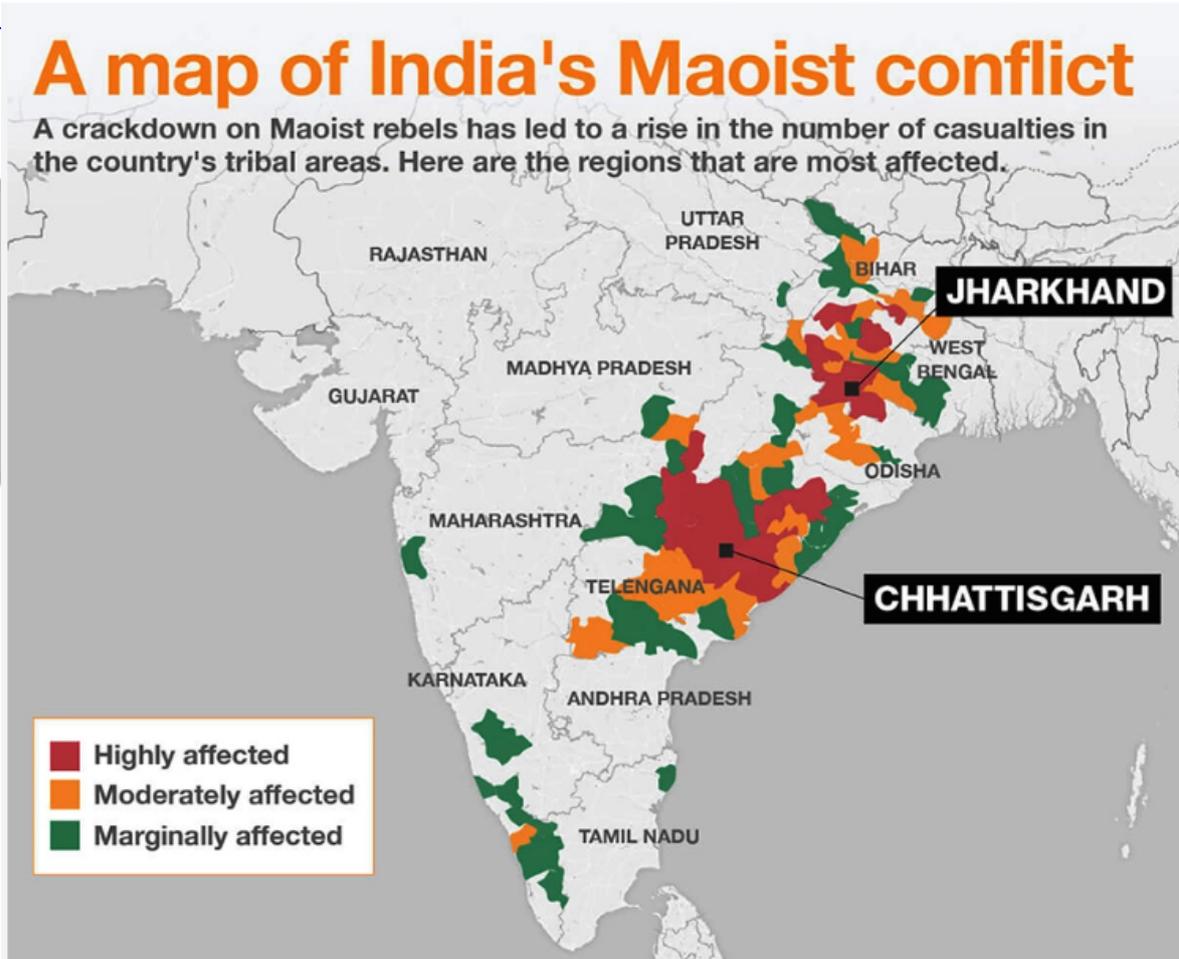
- शकियतों का समाधान: नक्षिपक्ष भूमि अधिग्रहण नीतियों को सुनिश्चित करना, [वन अधिकार अधिनियम, 2006](#) का कार्यान्वयन और सामाजिक-आर्थिक अंतर को कम करने के लिये जनजातीय अधिकारों का संरक्षण।

नोट: समाधान का अर्थ है S- Smart leadership (कृशल नेतृत्व), A- Aggressive strategy (आक्रामक रणनीति), M- Motivation and training (अभियेरेणा एवं प्रशक्तिषण), A- Actionable intelligence (अभियोज्य गुप्तचर व्यवस्था), D- Dashbord based key performance indicators and key result area (कार्ययोजना आधारित प्रदर्शन सूचकांक एवं परिणामोमुखी क्षेत्र), H- Harnessing technology (कारगर प्रौद्योगिकी), A- Action plan for each threat (प्रत्येक रणनीति की कार्ययोजना) और N- No access to financing (नक्सलियों के वित्त-पोषण को वफिल करने की रणनीति)।

माओवाद क्या है?

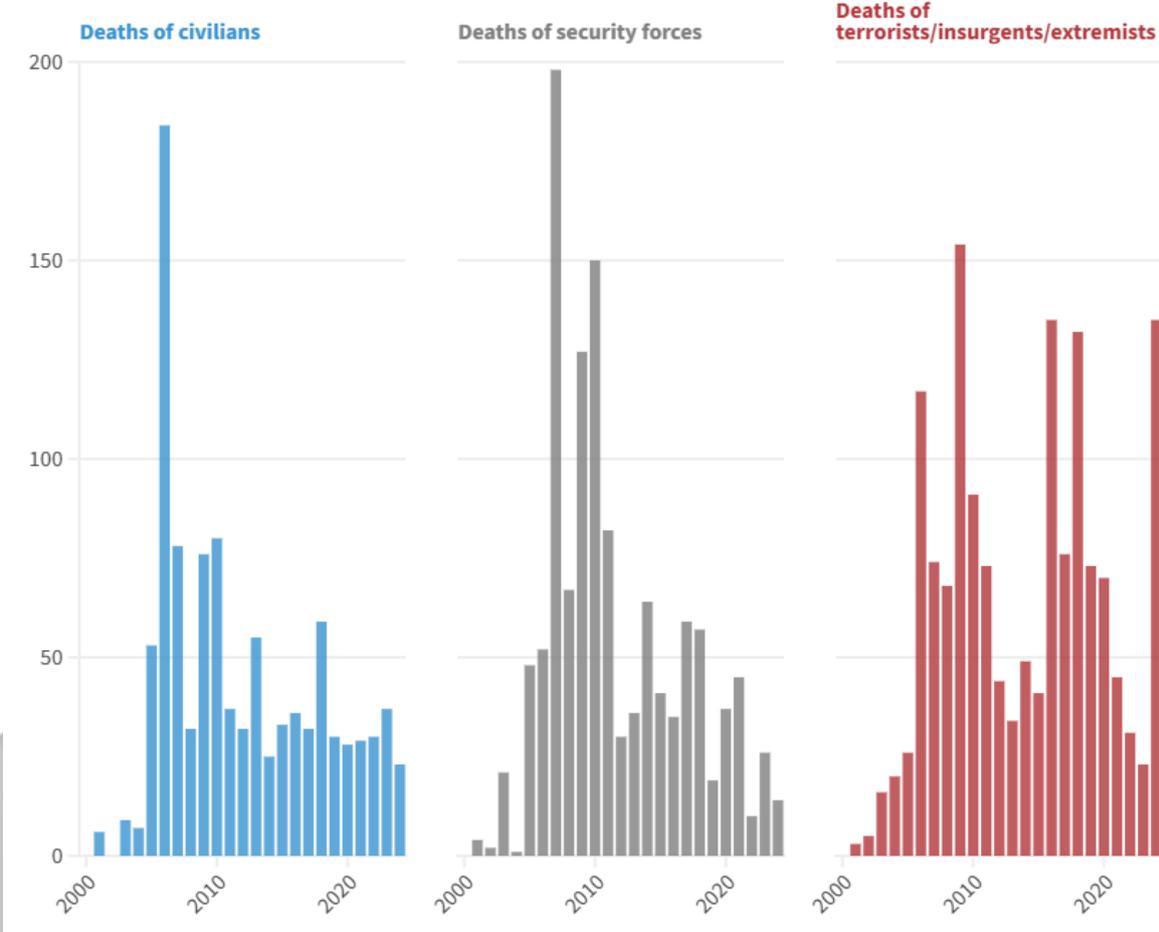
- **परिचय:** माओ से-तुंग द्वारा विकसित साम्यवाद का एक रूप है। यह सशस्त्र विद्रोह, जन-आंदोलन और रणनीतिक गठबंधनों के संयोजन के माध्यम से राज्य की सत्ता पर अधिकार करने का सिद्धांत है।
 - माओ ने इस प्रक्रिया को 'दीर्घकालिक जनयुद्ध' कहा, जिसमें सत्ता पर अधिकार करने के लिये 'मलिट्री लाइन' पर जोर दिया जाता है।
- **माओवादी विचारधारा:** माओवादी विचारधारा का केंद्रीय विषय राज्य सत्ता पर कब्जा करने के साधन के रूप में **हिसा और सशस्त्र विद्रोह** का प्रयोग करना है।
 - माओवादी उग्रवाद सिद्धांत के अनुसार, 'हथियार रखना अस्वीकार्य है'।
- **भारतीय माओवादी:** भारत में सबसे बड़ा और सबसे हसिक माओवादी संगठन **भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)** है जिसका गठन वर्ष **2004** में हुआ था।
 - फ्रंट ऑर्गनाइजेशन मूल माओवादी पार्टी की शाखाएँ हैं, जो कानूनी उत्तरदायित्व से बचने के लिये अलग अस्तित्व का दावा करती हैं।
- **CPI (माओवादी) और उसके अग्रणी संगठनों को गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, 1967** के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया है।

//



माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने में हाल की उपलब्धियाँ क्या हैं?

- **'माओवाद-मुक्त' गाँव:** वर्ष 2023 में छत्तीसगढ़ में **287 नक्सलियों** को मार गिराया गया, लगभग **1,000** को गरिफ्तार किया गया और **837** ने आत्मसमर्पण कर दिया।
 - **दंतेवाड़ा के गाँवों को क्रमिक रूप से 'माओवादी मुक्त'** घोषित किया गया है, वर्ष **2021 तक 15 से अधिक गाँवों** को यह दर्जा प्राप्त हो जाएगा।
 - रिकॉर्ड संख्या में नक्सलवादियों को मारा गया, गरिफ्तार किया गया या उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। यह इतिहास में पहली बार है कि एक ही वर्ष में इतना बड़ा क्षेत्र नक्सल प्रभाव से मुक्त हो गया है।



- **सुरक्षा बलों की मृत्यु में कमी:** वर्ष 2024 में, सुरक्षा बलों की केवल 14 मृत्यु दर्ज की गई, जो वर्ष 2007 में अधिकतम 198 मृत्यु की तुलना में काफी कम है।
- **समर्थन हासिल करना:** माओवादियों की असफलता का कारण जनजातीय समुदायों से **मलि रही समर्थन में कमी है**, जो वर्षों तक नुकसान पहुँचाने के बाद अलगाव महसूस कर रहे हैं।
- **उन्नत सुरक्षा उपाय:** सैन्य सहायता और परचालन दक्षता के लिये अब **12 हेलीकॉप्टर** तैनात किये गए हैं, जबकि पहले केवल दो हेलीकॉप्टर तैनात थे, जिसके बाद से सरकारी सैन्य हताहतों की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई है।
- **बुनियादी ढाँचा और रसद:** वर्ष 2014 और 2024 के बीच **544 कलिबंद पुलसि स्टेशन** बनाए गए, जबकि **वर्ष 2004 और 2014 के बीच केवल 66** ही बनाए गए थे।
 - सुरक्षा संबंधी रकित्तियों को भरने के लिये **45 पुलसि स्टेशनों** को भरने का नर्णय लिया गया है।
- **वर्षीय केंद्रीय सहायता:** अब तक कुल **14,367 करोड़ रुपए** स्वीकृत किये गए हैं, जिनमें से **12,000 करोड़ रुपए** प्रभावित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में सुधार पर खर्च किये गए हैं।

माओवादी उग्रवाद को समाप्त करने में क्या चुनौतियाँ हैं?

- **शोषण और दमन:** सामंती व्यवस्था, जातिपदानुक्रम और **वन संरक्षण अधिनियम, 1980** जैसे कानून ने आदवासियों को और अधिक अलग-थलग कर दिया, जबकि माओवादियों के मूल आधार जनजातियों तथा दलितों को ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहने के लिये मजबूर किया गया।
- **विकास का अभाव:** आंतरिक क्षेत्रों में **बुनियादी ढाँचे का अभाव है**, महत्त्वपूर्ण आवंटन के बावजूद शासन और कार्यान्वयन वफिलताओं के कारण विकास अवरुद्ध है।

- **केंद्रीकृत माओवादी कमान:** CPI (माओवादियों) के पास **केंद्रीकृत कमान** है, जो सरकार की **वभाजति प्रतिक्रिया** के कारण **अभुजमाध** जैसे क्षेत्रों को सैन्य ठिकानों के रूप उपयोग करने को सक्षम बनाती है।
- **समृद्ध संसाधनों तक पहुँच:** **80% कोयला भंडार** और लगभग **19%** अन्य समृद्ध **खनजि संसाधन** नक्सल प्रभावित आदवासी क्षेत्रों में स्थित हैं, जिससे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये एक अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- **वश्वास की कमी:** अप्रभावी शासन, संवैधानिक प्रावधानों (जैसे- **पाँचवीं एवं नौवीं अनुसूची**) के गैर-कार्यान्वयन तथा उचित पुनर्वास के बिना वस्थिापन से स्थानीय अलगाव की स्थिति और खराब हो जाती है।

आगे की राह:

- **शासन में सुधार:** **पाँचवीं अनुसूची** के अनुसार **जनजातीय सलाहकार परिषदों** का गठन करना ताकि आदवासियों को अपने संसाधनों के प्रबंधन में सशक्त बनाया जा सके।
 - भूमिहीनों को भूमि पुनर्वितरित करने के लिये **नौवीं अनुसूची** के अंतर्गत **भूमि हदबंदी अधिनियम** लागू करने की आवश्यकता है।
- **आर्थिक वकिस:** बुनियादी मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये **आक्रामक और समावेशी वकिसात्मक पहलों** पर ध्यान केंद्रित करना।
 - **अफीम की खेती** जैसी अवैध गतिविधियों पर निर्भरता को **कम करने** के लिये वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना।
- **सुरक्षा उपाय:** स्थानीय शासन संरचनाओं को सशक्त बनाते हुए जनजातीय क्षेत्रों को सुरक्षित करने के लिये **अर्द्ध-सैनिक बलों की विशेष इकाई** तैनात करना।
- **संसाधन प्रबंधन:** इस प्रक्रिया में हतिधारकों के रूप में आदवासियों के साथ **प्राकृतिक संसाधनों का सतत् और न्यायसंगत** दोहन सुनिश्चित करना।

प्रश्न:

माओवादी उग्रवाद को खत्म करने के लिये भारत सरकार द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली त्रि-आयामी रणनीतिक विश्लेषण कीजिये।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्षों के प्रश्न

प्रश्न:

Q. भारत के पूर्वी हिस्से में वामपंथी उग्रवाद के निर्धारक क्या हैं? प्रभावित क्षेत्रों में खतरे का मुकाबला करने के लिये भारत सरकार, नागरिक प्रशासन और सुरक्षा बलों को क्या रणनीति अपनानी चाहिये? (2020)

Q. पछिड़े क्षेत्रों में बड़े उद्योगों का वकिस करने के सरकार के लगातार अभियानों का परिणाम जनजातीय जनता और किसानों, जिनको अनेक वस्थिापनों का सामना करना पड़ता है, का वलिंगन (अलग करना) है। मलकानगरि एवं नक्सलबाड़ी पर ध्यान केंद्रित करते हुए वामपंथी उग्रवादी वचारधारा से प्रभावित नागरिकों को सामाजिक तथा आर्थिक संवृद्धि की मुख्यधारा में फरि से लाने की सुधारक रणनीतियों पर चर्चा कीजिये। (2015)